तरह-तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। सर, जब IAS, IPS या दूसरे अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने के बाद वे ट्रांसफर के बेस पर अगर कहीं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए एप्लाई करते हैं तो उनके पहले एडमिशन मिलता हैं लेकिन, सर, हम लोगों का यह दुर्भाग्य है, कि हम लोग यहां पर सांसद चुनकर आए और ट्रांसफर बेस पर जब हम अपने बच्चों के एडमिशनके लिए किसी पब्लिक या कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैंतो वहां दो-दो घंटे हम लोगों को खड़ा किया जाता है और प्रिंसिपल एडमिशन पर बात करने को तैयार नहीं होते।

सर, मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से कि जाए की ट्रांसफर बेस पर यदि कोई सांसद, जो कहीं दूर से चुनकर आते हैं, अगर अपने बच्चों के लिए कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सीट्स फिक्स कर दी जाएं और उनके बच्चों को वहां पर एडमिशन दिया जाए। यह मेरी मांग है।

Concern over spread of deadliest form of Malaria in India

SHR RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, although many steps have been taken to curb this deadliest disease of malaria in the country, still this disease is spreading more dangerously. There was a news item in the *Times of India* on the deadliest disease of malaria which is becoming more and more dangerous. Therefore, I request the Government to take appropriate steps to curb this deadliest disease in this counry. Thank you.

Suicide by Farmers in Vidharbha region of Maharashtra

श्री प्रकाश जावडेकर (महाराष्ट्र) **:** उपसभापति महोदय, आज जब "इसरो" के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी अंतरिक्ष में हासिल की है, तब जमीन पर कुछ बहुत दुखद हो रहा है। दुखद यह है कि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से तीन किसानों ने और आत्महत्या की है और किसानों की आत्महत्या का दौर बदस्तूर जारी है। 60 दिन पहले, 29 फरवरी को सरकार ने बड़े तामझाम से घोषणा की थी कि कर्ज माफी होगी और कर्ज् माफी की घोषणा की थी कि कर्ज् माफी होगी और कर्ज माफी की घोषणा के बाद लोगों को लगा और कुछ लोग दावा कर रहे थे कि अब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। लेकिन, किसान आत्महत्या कर रहे हैं।पिछले 54 दिनों में 162 किसानो ने आत्महत्या की है, जिनके नाम मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूं। यह क्यों हो रहा है ? यह केवल विदर्भ में ही नहीं, सभी जगह हो रहा है। क्योंकि, सरकार किसानों की जो मूल समस्या है, जो डिस्ट्रैस का मूल कारण है, उसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1998 में यानी 10 साल पहले, जब हम महाराष्ट्र में राज कर रहे थे, तब महाराष्ट्र में कपास के किसान को 2,500 रूपए का भाव मिलता था, लेकिन 10 सालों के बाद, जब उत्पादन की हर चीज का खर्चा बढ़ा है – दवा का, बीज का का, खाद का, हर चीज का खर्चा बढ़ा है, तब भी किसान को केवल 1,900 रूपए मिल रहे हैं, 2,000 रूपए मिल रहे हैं, यानी इन 10 सालों में जो भाव 2,500 रूपए से 3,500 रूपए तक हो जाना चाहिए था, वह आज 2,000 रूपए है। अगर कपास के किसान को हर क्विंटल पर हजार-बाहर सौ रूपए का नुकसान होगा, तो किसान कभी ऊपर नहीं आएगा, एक दफा कर्ज माफी करने से भी उसको लाभ नहीं होगा और विदर्भ को तो सरकारी शर्तो के कारण कर्ज माफी का लाभ वैसे भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज जो स्थिति पैदा हुई है वह भयावह है, क्योंकि कर्ज माफी की घोषणा केवल एक नारा मात्र बनकर रह गई है और किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसका जो मूल हक है, कि उसकी उपज का उचित दाम उसको मिलना चाहिए, उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वह आज नहीं मिल रहा है। मैं केवल एक आंकड़ा बताऊंगा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अभी आंकड़ा बताने का वक्त नहीं है, आपके पास केवल 28 सेंकड का समय बाकी है।

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, सरकार कपास की खरीद करती थी, हम साल भर में किसानों से 200 लाख क्विंटल से अधिक की खरीद करते थे और उनको तुरंत पैसा देते थे। अब जो सरकार आई, उसने किसान को रास्ते पर छोड़ दिया है और उसने 10 लाख क्विंटल कपास की खरीद तक नहीं की है। इस तरह से अगर चलेगा, तो किसान का क्या हाल होगा ? इसलिए इस और ध्यान देने की आवश्यकता है।